



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]
No. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1990/भाद्र 9, 1912
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1990/BHADRA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1990

विषय :—सी. जी. एल.-3 के अन्तर्गत कतिपय यान, फैब्रिक्स तथा मेडअप
मदों के उन देशों को होने वाले निर्यातों के संबंध
में मार्गदर्शी सिद्धान्तों, जहां पर ऐसे निर्यात कटौत
वर्ष 1991-93 के लिये माना संबंधी नियंत्रण के अधीन हैं।

(1) प्रस्तावना :

सं. 1/4/90-ईपी (टी ग्रेड जे) (वस्त्र)।—यान, फैब्रिक्स तथा मेडअप
के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आस्ट्रिया,
फिनलैंड, स्वीडन तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के संबंध में सी. जी. एल.-3
में दिये गये उपबन्धों के अनुसार, वर्ष 1991 से 1993 के लिये
हकदारियों के आवंटन संबंधी नीति (जिसे इसके बाद आवंटन नीति कहा
गया है) वह होगी जो इसमें इसके नीचे दी गई है। किन्तु बातों
के उल्लेख दौर के नतीजों और मध्य प्रदेश के भविष्य के आधार पर
आवश्यकतानुसार इस नीति में संशोधन का अधिकार सरकार के पास
सुरक्षित है।

235 GI/90

(2) प्रशासन :-

जब तक अन्यथा विदित न हो, सूची वस्त्र निर्यात संवर्धन
परिषद् (टेक्सप्रोमिल) के कार्यकारी निदेशक, ऊनी यान, फैब्रिक्स तथा
मेड अप्स को छोड़कर जिसके लिए आवंटन मंचित, उन तथा ऊनी
वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यूईपीसी) द्वारा किया
जाएगा, सभी यान, फैब्रिक्स तथा मेड अप्स संबंधी हकदारी निर्धारित
करेंगे। जबकि ऐसे सभी निर्यातों के लिए टेक्स-प्रोमिल आवश्यक
प्रमाण पत्र देगा।

(2) उपरोक्त प्रयोजन के लिए कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोमिल
तथा मंचित, उन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का अभिप्राय
ग्रह होगा और उसमें ऐसे अन्य अधिकारियों को शामिल करेंगे जिन्हें
वो ऐसे कार्य तथा उत्तरदायित्व अथवा अथवा पूर्णतः स्पष्टमया अथवा
अन्यथा प्रत्याभोजित करें।

(3) कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोमिल तथा मंचित, उन तथा ऊनी
वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् उनके द्वारा लागू किनी भी प्रत्याभोजन
के होने हुए भी इस आवंटन नीति के विप्रान्वयन के लिये वस्त्र मंत्रालय
के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(4) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के किन्हीं भा उपबन्धों का
निर्वाचन के संबंध में अन्तिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन

(1)

अधिकरणों, उनके कार्यों तथा बायिल्सों के संबंध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा बायिल्सों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुनर्बांटा कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(5) निर्यात हकदारियों का आर्बंटन कैंबल उम्हों निर्यातकों को किया जाएगा जो आयात-निर्यात नीति को अनुसार सही पंजीकरण प्राधिकारियों को पान पंजीकृत हो।

3. आधार अवधि :

किसी वर्ष के लिये "आधार अवधि" वाक्यांश इस अग्रसूचना में जहाँ कहीं आया हो, उसका अग्रिप्राय उन दो फेब्रुअरी वर्षों से होगा जो उस आर्बंटन वर्ष से एक दम पहले आए हों। उदाहरणार्थ वर्ष 1991 के लिये आधार वर्ष 1988 तथा 1989 के वर्ष होंगे।

4. आर्बंटन की प्रणाली :

प्रत्येक आर्बंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आर्बंटन निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार उनके सामने विनिर्दिष्ट दरों पर खण्ड 16 के अध्याधीन किया जायेगा।

प्रणाली	वार्षिक स्तर की प्रतिशतता
क. विगत कार्य निष्पादन हकदारी (पीपीई)	40%
ख. संविदा आरक्षण हकदारी (सीआरई)	25%
ग. सरकारी खेज हकदारी (पीएसई)	3%
घ. पहले आधो पहले पाधो प्रणाली (एफसीएफएस)	20%
ङ. विनिर्माता निर्यातक हकदारी प्रणाली	12%
योग	100%

(1) उपरोक्त के अलावा, अध्ययनों, लोचशीलताओं अथवा अध्ययन के परिणामस्वरूप समय-समय पर जो मात्रा उपलब्ध होगी उसका आर्बंटन भी पहले आधो पहले पाधो की प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) माँग पेटेंट में परिवर्तनों को देखते हुए यदि बांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियाँ आर्बंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित है।

5. भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, यह विनिश्चय कर सकता है कि यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि पहले आधो पहले पाधो प्रणाली के लिए या तो मूल आर्बंटन द्वारा अथवा अध्ययन/लोचशीलता आदि के कारण निर्धारित किसी भी मात्रा को अंशतः अथवा पूर्णतया किसी ऐसी दूसरी प्रणाली से आर्बंटित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

6. आर्बंटन :

आर्बंटन का उपयोग करने के लिये पीपीई, सी आर ई तथा पी एस ई के लिये वर्ष को दो अवधियों में बाँट दिया जायेगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मार्च तक होगी। दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। कम से कम 50% आर्बंटनों का पहली अवधि के दौरान उपयोग किया जायगा और शेष का दूसरी अवधि के दौरान एक सी एक एस की वैधता अवधि 90 दिन होगी, लेकिन 31 दिसम्बर के बाद नहीं होगी। किसी भी हकदारी का उपयोग न किया गया भाग खण्ड 7, 8, 9 तथा 12 के अध्याधीन प्रत्येक अवधि के अन्त में स्वतः अभ्यर्पित हो जायेगा।

(1) उपर्युक्त प्रणालियों में निर्धारित मात्राएं पहली अवधि में रिलीज की जायेगी। जहाँ तक संभव होगा ये मात्राएं पहली जनवरी को भी जायेंगी और इस प्रयोजन के लिये आवेदन पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आमंत्रित किए जा सकते हैं।

(2) एक ई एक एस प्रणाली के तहत सम्पूर्ण मात्रा आर्बंटन वर्ष के आरम्भ में उपर्युक्त धारा 4(2) के अध्याधीन दी जाएगी और इस कार्य के लिये आवेदन पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आमंत्रित कर सकता है।

7. विगत निष्पादन हकदारी (पीपीई)

(1) पीपीई के परिकलन के लिये अभिकरण कार्यकारी निदेशक टैक्स प्रोसिल होगा। परिकलन निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा।

(2) उपलब्ध स्तरों का आर्बंटन आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक वेग/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर समानुपात किया जाएगा तथापि आर्बंटन को आधार अवधि के दौरान उक्त वेग/श्रेणी में भारत के वार्षिक प्रोसिल निष्पादन की सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

(3) पीपीई की मूल वैधता अवधि के दौरान पीपीई को पूर्णतः या अंशतः हस्तांतरित किया जा सकता है।

(4) हस्तान्तरित पीपीई (जिसे पहले वह पीपीई कहा जायेगा) उक्त आर्बंटन अवधि के लिये वैध होगा। जिसमें हस्तांतरण लागू हुआ है।

(5) पीपीई के आधार पर दोन सक्षमों का समतः अंतरणकारी द्वारा किये गये निर्यात के रूप में की जायेगी।

(6) पीपीई के अंतरण की अनुमति नहीं है।

(7) बड़ाई गई अवधि के दौरान पीपीई के अंतरण की (धारा 7 (2) अथवा पैरा 12(2) के अन्तर्गत अनुमति नहीं है।

8. पीपीई का अभ्यर्पण एवं बिलान

(1) पहली अवधि के दौरान उपयोग में न जाई गई मात्रा स्वतः अभ्यर्पित की जायेगी।

(2) तथापि, दूसरी अवधि के दौरान उपयोग में न जाई गई मात्रा को नीचे उप पैरा (3) में उल्लिखित दर पर ईएमबी/बी.जी. द्वारा पृष्ठांकित आयात पत्र के आधार पर 31 दिनांक तक बड़ाया जा सकता है।

वैधता की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन पत्र टैक्स प्रोसिल के पास हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान अवश्य पहुँच जाने चाहिये।

(III) ई.एम.बी./बी.जी. को दर निम्नानुसार होंगे :—

वस्तु	दर
(क) ई.ई.सी./संयुक्त राज्य अमरीका कोयाने	4.50 रुपये प्रति कि.ग्रा.
(ख) ई.ई.सी., स्वीडन तथा नार्वे को फेब्रिक तथा मैड-अप्स	8.00 रुपये प्रति कि.ग्रा.
(ग) अमरीका तथा कनाडा को फेब्रिक तथा मैड-अप्स	2.00 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड अथवा 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर जैसा भी मामला हो।
(घ) कोई अन्य वस्तु	एफ.बी.बी. मूल्य का 20%

9. संविदा आरक्षण प्रणाली (सी.आर.ई.)

(i) सी.आर.ई. के आर्बंटन के लिये निर्धारित की अवधि आवेदन पत्र के साथ एक फॉर्म आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसकी उपर्युक्त सी.-17(3) के अनुसार ई.एम.बी./बी.जी. द्वारा पुष्टि की गई हो।

(ii) सी.आर.ई. आर्बंटन हस्तांतरणीय नहीं होगा।

(iii) सी.आर.ई. के उपयोग के लिये वर्ष का दो अवधियों में बाँटा जायेगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मई तक होगी तथा

दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। माबंटन का कम से कम 5% भाग पहली अवधि के दौरान उपयोग किया जावेगा तथा शेष दूसरी अवधि के दौरान। पहली अवधि के दौरान जिस मात्रा का उपयोग नहीं होता है बहुस्तरीय समाप्त हो जायेगा।

(iv) तथापि दूसरी अवधि के लिये निर्धारित की गई मात्रा की वैधता पैरा 7(3) के निर्धारित बरों के आधार पर ई.एम.जी./बी.जी. द्वारा समर्पित अधिपक्ष के आधार पर 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा सकती है। वैधता अवधि बढ़ाने संबंधी आवेदन पक्ष टेक्सप्रोसिल को हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

(v) नियमित प्रतिवार कर से उत्पन्न उत्प्रेरक (1) में उल्लिखित आदेश के आधार पर किया जायेगा।

(vi) मात्रा का माबंटन पहले प्राप्ति पहले प्राप्ति के आधार पर किया जायेगा। बस्त्र आयुक्त अधिकतम मात्रा निर्धारित कर सकते हैं जिसके लिये प्रत्येक आवश्यक देश/क्षेत्रों के लिये आवेदन किया जा सकता है।

अगर किसी खास दिन, अगर कुल मात्रा जितने निर्देश आवेदन किया गया है, वितरण हेतु उपलब्ध मात्रा से अधिक है तो उस दिन मात्रा प्राप्त आवेदन-पत्रों में उच्चतर इकाई मूल्य के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

10. सरकारी बोल की हकदारी (पी.एच.ई.)

(i) केन्द्र/राज्य सरकार के निबंधनाधीन निगमों और गोप्य सहकारी संस्थानों के लिये जो केन्द्र/राज्य स्तर पर विनिर्माण कर रहे हैं, के लिये 3% का निर्धारण होगा।

(ii) बस्त्र आयुक्त ऐसे आवेदकों की मात्रा तथा अमरा का मूल्यांकन करेंगे।

(iii) ई.बी. टेक्सप्रोसिल, बस्त्र आयुक्त द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर कोटा आबंटित करेगा।

(iv) पी.एच.ई. की वैधता तथा वैधता अवधि बढ़ाने का वहां व्यवस्था होगी, जो सी.आर.ई. के लिये है।

11. पहले प्राप्ति पहले प्राप्ति (एफ.सी.एफ.एस.)

(i) ई.एम.जी./बी.जी. के आधार पर पहले प्राप्ति-पहले प्राप्ति के आधार पर मात्रा आबंटित की जायेगी।

(ii) बस्त्र आयुक्त अधिकतम मात्रा निर्धारित करेंगे जिसके लिये अगर बस्त्र आयुक्त ऐसा करना आवश्यक समझें तो एक विनियम एक दिन में एफ.सी.एफ.एस. के अखीन प्रत्येक देश/क्षेत्रों के लिये आवेदन दे सकते हैं।

(iii) इस व्यवस्था के अंतर्गत माबंटन 90 दिनों के लिये वैध रहेगा, लेकिन माबंटन-वर्ष के 31 दिसम्बर के बाद नहीं। यह व्यवस्था पैरा 12 के अनुसार है।

(iv) ई.एम.जी./बी.जी. जिनके लिये आवेदन किया गया है—की दर, एक प्राप्ति मूल्य की 5% होगी।

(v) किसी विशेष दिन जब उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा आबंटित होती है, मात्रा उस तारीख को प्राप्त आवेदन पत्रों के बीच उच्चतर इकाई मूल्य आधार पर निर्धारित की जायेगी।

12. विनिर्दिष्ट निर्वातक हकदारी प्रणाली :

(i) इस प्रणाली के अंतर्गत माबंटन उन्नतिनिर्माता निर्वातक को किया जायेगा जिन्होंने आधार अवधि के दौरान आवेदन किया था।

मशीनरी में ठोस रूप से प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया है। मात्रा के नियम तथा माबंटनी सिद्धांतों को बस्त्र आयुक्त द्वारा, अलग से अधिसूचित किया जायेगा।

(ii) इस प्रणाली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्वातक को मात्रा तथा उत्पादन क्षमता निर्धारित करने का प्राधिकार बस्त्र आयुक्त को होगा।

(iii) इस व्यवस्था के अंतर्गत माबंटन केवल उन्हीं वस्तुओं के लिये होगा, जिसका विनिर्माण बस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन उत्पादन एकक में होगा।

(iv) उपलब्ध मात्रा, बस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये पाठ आवेदकों को उत्पादन क्षमता के आधार पर कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल द्वारा, विनियमित की जायेगी। उपर्युक्त आवेदन हेतु प्रत्येक पक्ष आवेदक अधिक से अधिक 15 देशों/क्षेत्रों का चयन कर सकता है।

(v) अवकाशों की देश/क्षेत्रों में किसी आवेदक को आबंटित की गई मात्रा (बस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित) बहुत ज्यादा कम होती है, कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल आवेदक के आबंटित मात्रा पर्याप्त हो।

(vi) इस व्यवस्था के अंतर्गत माबंटन अस्थायित्वपूर्ण नहीं है। प्राप्ति करने की पुष्टि के समय एक हलफनाम प्रस्तुत करेंगे कि निर्वात की जा रही वस्तुओं का विनिर्माण उन उत्पादन एककों में हुआ है, जिनका आधुनिकीकरण उन्नयन हो गया है।

(vii) इस व्यवस्था के अंतर्गत माबंटन के लिए क्षेत्रों की न्यूनतम कीमतें बस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से निर्धारित की जायेगी।

13. न्यूनतम कीमत

इन चारों व्यवस्थाओं के अंतर्गत बस्त्र आयुक्त न्यूनतम कीमत निर्धारित करेंगे। न्यूनतम कीमत निर्धारित करते समय आधार अवधि के दौरान औसत इकाई मूल्य तथा विनिर्माण बरों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जायेगा।

14. प्रमाणन/पील सबान

(1) माबंटन की सभी प्रणालियों के अंतर्गत टेक्सप्रोसिल द्वारा प्रमाणन की वैधता 30 दिनों के लिए होगी।

(2) माबंटन की सभी प्रणालियों में, प्रमाणन की वैधता उपर्युक्त पैरा 7(3) में उल्लिखित बरों की 50% की प्रतिरिक्त ई.एम.जी./बी.जी. और एफ.सी.पी.एस. के लिए पैरा 10(4) में उल्लिखित मात्रा जिसके लिए ऐसी समय-वृद्धि मांगी जाती है, टेक्सप्रोसिल को प्रस्तुत करके टेक्सप्रोसिल द्वारा और 30 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती। समय वृद्धि के लिए सभी आवेदन पक्ष टेक्सप्रोसिल के पास मूल प्रमाणन की वैधता अवधि के दौरान टेक्सप्रोसिल के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। (3) दिनांक 31 दिसम्बर के बाद न तो मूल प्रमाणन और न ही समय वृद्धि प्राप्त प्रमाण-पत्र वैध होगा।

15. कम कारोबार वाली मचें

(1) एक मच की कम कारोबार वाली मच के रूप में सभी अधिसूचित किया जाएगा यदि आधार अवधि के प्रत्येक वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षों के लिए उपयोग आधार मूल स्तर के 75% से कम रहा है। बि.ई.टी. टेक्सप्रोसिल उन मचों को अधिसूचित करेगा जो अधिक से अधिक पिछले वर्षों के 1 दिसम्बर से कम कारोबार वाली मचें हैं।

(2) इस अधिसूचना के किसी प्रावधानों में कोई अन्य व्यवस्था सहित होते हुए भी कम कारोबार वाली मच के लिए सामान्यतः निर्धारित छूट दी जाएगी।

(क) एक सी एक एस के अंतर्गत आवश्यक एक सी का कोई निर्धारण नहीं होगा।

(ख) १ एस डी/बी जी की दर एक सी की मूल्य के 1% होगा।

(3) किन्तु उपर्युक्त छठ अधिन सूचना के बिना वापस ली जा सकेगी।

16(1) एक निर्यातक जो पी पी ई एक सी एड एस सा आर ई के अंतर्गत किसी विशेष अवधि में अथवा पी पी ई एक सी एक एस सी आर ई या पी एस ई सहित पी पी ई के लिए समयवृद्धि के दौरान निर्यात वायव्यता के 90% से कम निर्यात करता है तो जैसी कि शर्त है उसके बाद उसकी ई एस डी/बी जी को अस्त कर दी जाएगी। ई डी/टेक्सप्रोमिल ई एस डी/बी जी को उस शालत में ज्वल कर लेगा यदि अधिक कारोबार वाली भंडों के मामले में उपयोग 75% तक है और कम कारोबार वाली भंडों के मामले में 50% तक है जो कि उपयोग में गिरावट के अनुपात में है।

यदि उपयोग उपर्युक्त में कम है तो ई एस डी/बी जी को पूरी तरह से ज्वल कर लिया जाएगा।

(2) इस उद्देश्य के लिए उपयोग का प्रत्येक देश/क्षेत्रों के लिए प्रत्येक प्रगती और अवधि के आधार पर प्रत्येक से परिकल्पित किया जाएगा। वैधता/प्रमाणन का समय बढ़ाने के मामले में प्रतिशतता उपयोग को उस मात्रा के लिए प्रत्येक प्रत्येक परिकल्पित किया जाएगा जिसके लिए प्रमाणन/वैधता का बढ़ाया गया है।

(3) सभी जहाँ ई एस डी/बी जी को सरकार के पी पी खाने में जमा कर दिया जाएगा। और उसका प्रभाव इस प्रकार होगा जैसा सरकार समय समय पर अधिसूचित करे।

(4) जिस व्यक्ति को निर्यात हकदारी आवंटित की जाती है लेकिन जो इसका पूरी तरह उपयोग नहीं करते हैं तो उनके निर्यात की जा रही किसी कार्रवाई के संबंध में कोई पूर्वग्रह अपनाया बिना भविष्य में इस हकदारी के लिए आयोज्य घोषित किए जाने के स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) जवनी के पूर्व कारण अनायास मोटिव जारी किया जाएगा।

17. ई एस डी/बी जी की जवनी के खिलाफ अपील :

एक निर्यातक को जब उपर्युक्त 14 के अंतर्गत ई डी टेक्स-प्रोमिल द्वारा अर्द्धा के आदेश द्वारा हानि पहुंचती है तो वह जवनी संघी ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अपीलकेदन प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करेगा। अपील को निपटाने समय वह प्रभावी प्रमुख शर्तों यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखेगा। वह उनकी वैधता के दौरान, अनुपयुक्त हकदारियों को सीपने में सतर्कता को भी ध्यान में रख सकता है। इस उद्देश्य के लिए वस्त्र आयुक्त स्वयं द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी को शामिल कर सकेगा और उन्हें माध्यम बना सकेगा अपीलकर्ता द्वारा अनुग्रह किए जाने पर वह व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे सकता है।

18. हथकरघा उत्पाद

उपर अन्यत्र उल्लिखित किसी भी शर्त के होते हुए हथकरघा उत्पादों के लिए निम्नलिखित आधार पर कटे का आवंटन किया जाएगा।

प्रणाली	प्रतिशतता
पी पी ई	10%
एक सी एक एस	30%
सी आर ई	30%

(2) पी पी ई तथा एक सी एक एस की लिए जैसे आवश्यक तिर-बन्धन सहित हथकरघा कोटा हनु गामास्य तार पर लागू होगी।

(3) इस नीति के विशिष्टकरण का निरीक्षण करने के लिए हथकरघा कोटा प्रशासनिक समिति होगी। इसमें हथकरघा उत्पादों के लिए लागू प्रावधानों और नीतियों में डील देना भी शामिल होगा।

(क) उपा सचिव/निरीक्षण (निर्यात) —प्रत्यक्ष

(ख) ई डी (टेक्सप्रोमिल) —सदस्य

(ग) ई डी एक ई पी सी —सदस्य

(घ) वस्त्र आयुक्त अथवा उसका प्रतिनिधि —सदस्य

(ङ) सचिव वस्त्र समिति या उनकी प्रतिनिधि —सदस्य

(च) जे डी सी (हथकरघा) —सदस्य

(4) एक सी एक एस कोटा 10% तक एक वस्त्र एस सी द्वारा पी एस ई एस के लिए आवंटित होगा।

19. सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण

(1) प्रतिबंधाधीन उत्पाद

पोतलदान पलत पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान का अनुमति मूल रूप में निर्यात हकदारी प्रमाणन और अलग-अलग प्रेषण क्षेत्रों के लिए टेक्सप्रोमिल या इस उद्देश्य के विनिर्दिष्ट किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी द्वारा जारी पोत परिवहन विलों की अनौखिप के सत्यापन के बाद दी-वी जाएगी।

(2) हथकरघा उत्पाद :

जहाँ तक प्रतिबंधित भंडों के नमूने सभी हथकरघा फैब्रिकों/मिश्र वस्त्र के निर्यात का संबंध है सीमाशुल्क अधिकारी पोतलदान की अनुमति काम्प्लेशन फार्म के पैरा-2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पंठाकन" के आधार पर देखी।

(3) "इंडिया आइटम्स" के प्रत्येक भाग बांटे में ड-अंश

"इंडिया आइटम्स" को भारत के परम्परागत लोकगीत के हस्तनिर्मित वस्त्र उत्पाद है, के बारे में यू एस ए, ई ई सी कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड और नार्वे को निर्यात के लिए सीमा शुल्क अधिकारी पोतलदान की अनुमति विकास आयुक्त (हस्तनिर्मित) कार्यालय द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाणपत्रों के आधार पर देगे।

20. निर्यात प्रमाण पत्र उद्भव प्रमाण :

गैरग द्वितीय वस्त्र काल के प्रयोग अश्वित निम्नलिखित प्रमाणन टेक्सप्रोमिल या उसकी और गे बिबिध प्राधिकृत वस्त्र एजेंसी द्वारा जारी किए जाएंगे।

(1) यू एस ए

बाणिज्यिक मूल्य के सभी मिलनिर्मित पावरलूम फैब्रिकों और मेड-अंश भंडों के लिए सीमा और कर्ष विभाजन को छोड़कर हथकरघा मेड-अंश के लिए सीमा।

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(क) पावरलूम/मिश्र निर्मित वस्त्रों की सभी प्रतिबंधित भंडों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र तथा उद्भव प्रमाण पत्र।

(ख) पावरलूम/मिश्र निर्मित/बुने हुए वस्त्रों की प्रतिबंधित भंडों के लिए उद्भव प्रमाण पत्र।

(3) कनाडा

मिल-निर्मित/पावरलूम/बुने हुए प्रतिबंधित वस्त्रों फैब्रिकों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र, सिर्फ ऐसे भाग को छोड़कर जिसका मूल्य 5.00 कनाडियन डॉलर से कम है।

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1990

Subject: Guidelines for exports under OGL-3 of certain yarn, fabrics and made-up items to countries where such exports are under quantitative restraint for the calendar years 1991-93.

(1) Introduction:

No. 1/4/90-EP(I&J)(Textiles).—In pursuance to provisions contained in OGL-3 in respect of export of yarn, fabrics and made-ups to USA, Canada, EEC, Austria, Finland, Sweden and Norway, the policy for allotment of entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 1991-1993 shall be as hereinafter provided. However, depending upon the outcome of the Uruguay Round of Negotiations and the future of M.F.A., Government reserves the right to amend the policy, as necessary.

(2) Administration:

Unless otherwise directed, the Executive Director, Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) shall allocate entitlement for all yarn, fabrics and made-ups except for woollen yarn, fabrics and made-ups for which allotment will be made by the Secretary, Wool and Woollen Export Promotion Council (W&WEPC). However, necessary certification for all such exports shall be done by TEXPROCIL only.

(ii) For the purpose of the above the Executive Director, TEXPROCIL and Secretary, W&WEPC shall mean and include such other officials to whom they expressly or otherwise delegate part or whole of their functions and responsibilities.

(iii) The ED TEXPROCIL and the Secretary, W&WEPC, notwithstanding any delegation effected by them, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the policy.

(iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guide lines as it deems fit from time to time, regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

(v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities under the Import-Export Policy.

(3) Base Period:

The phrase "Base period" for an allotment year wherever appearing in this Notification shall mean the two calendar years preceding the year immediately before that allotment year. For example the base period for the year 1991 shall be the years 1988 and 1989.

(4) Systems of Allotment:

Quantities for export in each allotment year shall be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them subject to Cl. 16.

System	Percentage of Annual Level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	40%
(b) Contract Reservation Entitlement (CRE)	25%
(c) Public Sector Entitlement (PSE)	3%
(d) First Come First Served (FCFS)	20%
(e) Manufacture Exporter Entitlement (MEE)	12%
Total:	100%

(1) आशुतथा

विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित वस्तुओं के फैब्रिक/मेडअप के निर्यात प्रमाण पत्र।

(2) स्वाधेन

परिमाणविक प्रतिबंधों के अन्तर्गत फैब्रिक/मेडअप/यार्न वस्तुओं के निर्यात प्रमाण पत्र।

(3) नार्थ

अर्थात् 7 के अन्तर्गत पावरलूम तथा मिश्र निर्मित वस्तुओं के निर्यात प्रमाण पत्र।

2.1 हथकरघा और छोट प्रमाण पत्र

कनारा का प्रतिनिधित्व तथा वे पिछले कुल हथकरघा फैब्रिक/मेडअप/यार्न का गुटी हथकरघा वस्तु फैब्रिक/मेडअप, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा स्थान राज्य प्रमोटींग बोर्ड की हथकरघा वस्तु तथा मेडअप एवं नाय को यथास्थिति का निर्यात के मामले में वस्तु समिति ऐसे उत्पादों के निर्यात दिवसावधि कार्यों में तथा निर्धारित प्रमाण पत्र जारी करेगी।

2.2 सरकार का बिना पूर्व सूचना के किसी भी पूर्ववर्ती व्यवस्था में सुधार करने का अधिकारी होगा।

2.3 संबंधित निर्यात संस्थाओं परियोजना तथा वस्तु प्राप्ति, वस्तु समिति तथा विकास आयुक्त (हस्तनिर्मित) के कार्यालयों के पते निम्नानुसार हैं :-

1. वस्तु प्राप्ति का कार्यालय,

न्यू सीजी ओ बिल्डिंग

न्यू डीरीन लाइन्स,

पोस्ट-बॉक्स नं. 11500

बम्बई-400020

2. गुटी वस्तु निर्यात संस्था परियोजना,

इंजीनियरिंग सेंटर,

बुल्लो नगर, 9 न्यू रोड

बम्बई-40004

3. सिविल तथा रेल वस्तु निर्यात संस्था परियोजना,

विश्व भवन, चार नरामन रोड,

बम्बई-400020

4. ऊन तथा ऊनी वस्तु निर्यात संस्था परियोजना,

612/714, अणुका इस्टेट

24 बारा रोड

नई दिल्ली-110001

5. काशी निर्यात संस्था परियोजना,

बुकान नं. बी-115, मेक्टर-18,

पोस्ट ऑफिस नं. 10,

जिला-गायिकाबाद

6. विकास आयुक्त (हस्तनिर्मित)

वेस्ट ब्लॉक नं. 7, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली-110066

7. टैक्सटाइल समिति,

"फिक्स्टल"

79 डॉ. एन. थिमेन्ट रोड,

बम्बई

बम्बई-40000

(ii) Apart from the above, quantities that become available time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under FCFS System.

(iii) Government of India in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above in case it is considered so desirable in view of changes in demand patterns.

5. Government of India in the Ministry of Textiles may decide, if so satisfied, that part or whole of any of the quantities earmarked for FCFS either by way of original allocation or on account of surrender/flexibilities etc., shall be allotted in such other manner as it deems fit:

(6) Allotments :

(i) For the purpose of utilisation of allotments, the year shall be divided into two periods for PPE, CRE and PSE. The first period shall be from 1st January to 31st May. The second period shall be from 1st June to 30th September. A minimum of 50 per cent of the allotments shall be utilised during first period and the balance during the second period. The validity period of FCFS shall be 90 days, but not beyond 31st December. The unutilised portion of any entitlement shall stand automatically surrendered at the end of each period subject to Cl. 7, 8, 9 and 12.

(ii) The quantities earmarked in the above systems shall be released in the first period. As far as possible, the quantities shall be opened on 1st January and for this purpose applications may be invited during the previous year.

(iii) The entire quantity under FCFS system shall be opened at the beginning of the allotment year [subject to clause 4(ii) above] and for this purpose applications may be invited during the previous year.

(7) Past Performance Entitlement (PPE) :

(i) The agency for computation of PPE shall be E.D., TEXPROCIL. Computation shall be done in the following manner.

(ii) Available levels will be allotted pro-rata on the value of exports during the base period by the applicants in each country/category. Allotments, however, will be restricted to the average annual export performance of India in the country/category during the base period.

(iii) PPE shall be transferable, either in full or in part, during the period of original validity of PPE.

(iv) A transferred PPE (hereinafter referred to as PPT) shall be valid for the allotment period for which the transfer is effected.

(v) Shipments against PPT shall be counted as exports by the transferee.

(vi) Transfer of a PPT is not allowed.

(vii) Transfer of PPE during the period of extension (i.e. either under Cl. 7(ii) or Cl. 12(ii)) is not allowed.

(8) Surrender and Extension of PPE :

(i) The quantity not utilised during the first period shall be automatically surrendered.

(ii) Validity of the quantity not utilised during second period, however, can be extended upto 31st December against letter of credit backed by EMD/BG at the rate mentioned in Sub-Clause (iii) below. An application for extension of validity must reach TEXPROCIL during the period of original validity of the entitlement.

(iii) The rate of EMD/BG shall be as follows :

Item	Rate
(a) Yarn to EEC/USA	Rs. 4.50 per kg.
(b) Fabrics and made-ups to EEC, Sweden and Norway.	Rs. 8.00 per kg.

(c) Fabrics and made-ups to USA and Canada.	Rs. 2/- per sq. yd. or Rs. 2/- per dozen as the case may be.
(d) Any other item.	20% of FOB value

(9) Contract Reservation System (CRE) :

(i) For allotment of CRE, the exporter will have to submit alongwith his application, a firm order, backed by EMD/BG prescribed at Cl. 8(iii) above.

(ii) A CRE allotment shall be transferable.

(iii) For the purpose of utilisation of CRE, the year shall be divided into two periods. The first period shall be from 1st January to 31st May and the second period shall be from 1st June to 30th September. At least 50 per cent of the allotment shall be utilised during the first period and the balance during the second period. Any quantity not utilised during the first period shall stand automatically surrendered.

(iv) Validity of the quantity earmarked for the second period, however, can be extended upto 31st December against letter of credit backed by EMD/BG at the rates prescribed at para 8(iii). An application for extension of validity must reach TEXPROCIL during the period of original validity of the entitlement.

(v) Exports shall be necessarily made against order referred to in Sub-clause (i) above.

(vi) Quantities shall be allotted on first come first served basis. Textiles Commissioner may fix the maximum quantity that can be applied for each country/category, if necessary. If on a particular day, the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation amongst applications received on the day.

(10) Public Sector Entitlement (PSE) System :

(i) For corporations under the control of Central/State Governments and Apex Cooperatives of Central/State level who have manufacturing units there shall be an allocation of 3 per cent.

(ii) The Textile Commissioner shall assess the eligibility and capacity of such applicants.

(iii) The E.D., TEXPROCIL shall allot quota in accordance with the assessment made by the Textiles Commissioner.

(iv) The provisions of validity and extension of validity of PSE shall be the same as that for CRE.

(11) First Come-First Served (FCFS) System :

(i) Quantities shall be allocated on first come first served basis against EMD/BG.

(ii) Textile Commissioner may fix the maximum quantity that can be applied for each country/category under FCFS by an exporter in one day if the Textile Commissioner feels it necessary to do so.

(iii) Allotments under this system shall be valid for a period of 90 days, but not beyond 31st December of the allotment year subject to Clause 14.

(iv) The rate of EMD/BG shall be 5 per cent of FOB value applied for.

(v) On a particular day when available quantities are over-subscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on this particular date.

(12) Manufacturer Exporter Entitlement System :

(i) Allotment under this system shall be made to Manufacturer-Exporters who have undertaken substantial modernisation and upgradation of technology in their plant and machinery during the base period. Guidelines and norms of eligibility will be separately notified by the Textile Commissioner.

(ii) The Textile Commissioner shall be the authority to decide the eligibility and production capacity of the Manufacturer-Exporters within the meaning of this system.

(iii) Allotment under this system shall be only in respect of goods manufactured in the production unit modernised and upgraded as determined by the Textile Commissioner.

(iv) Available quantity will be distributed by the Executive Director, TEXPROCIL on the basis of production capacity of eligible applicants as decided by the Textile Commissioner. Each eligible applicant may opt for a maximum of 15 country/categories for the above allotment.

(v) When the quantity allotted to any applicant in any one country/category is too small (as decided by the Textile Commissioner), the Executive Director, TEXPROCIL shall reallocate such quantity in such a manner that the quantities allotted to each of the applicants is reasonable enough.

(vi) Allotments under this system are not transferable. The allottees shall, at the time of certification of shipments submit an affidavit that goods being exported have been manufactured in his production unit so modernised/upgraded.

(vii) Floor prices in respect of categories for allotments under this system shall be separately prescribed by the Textile Commissioner.

(13) Floor Price

Under all the five systems, Textile Commissioner shall fix floor prices. While fixing floor price, the average unit value realisation during the base period and the fluctuations in exchange rates shall be taken into consideration.

(14) Certification/Shipment

(i) The validity of certification by TEXPROCIL under all systems of allotment shall be for a period of 30 days.

(ii) In all systems of allotment, extension of the validity period of certification can be extended by another 30 days by TEXPROCIL by furnishing to TEXPROCIL an additional EMD/BG of 50 per cent of the rates mentioned in para 8(iii) above and para 11(iv) of FCFS for the quantity for which such extension is sought. All application for extension must reach TEXPROCIL during the period of validity of the original certification.

(iii) Neither the original certification nor the extended certificate shall be valid beyond 31st December.

(15) Slow-moving items

(i) An item shall be notified as slow-moving if during each of the years of the base period the utilisation has been less than 75 per cent of the base level for the corresponding years. The ED, TEXPROCIL shall notify the items that are slow-moving latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notifications, the following relaxations shall be ordinarily available for a slow-moving item :

(a) There shall be no stipulation of compulsory L.C. under FCFS.

(b) The rate of EMD/BG shall be @ 1% FOB Value.

(iii) The above relaxations may, however, be withdrawn without advance notice.

(16) (i) The BG of an exporter who exports less than 90 per cent of the export entitlement in a particular period under PPE, FCFS, CRE or during the extension of PPE including PPT, FCFS, CRE or PSE shall be forfeited as hereinafter provided. The ED, TEXPROCIL shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is upto 75 per cent in case of fast moving items and upto 50 per cent in case of slow-moving items proportionate to the shortfall in utilisation. If utilisation is less than the above, the EMD/BG shall be forfeited in full.

(ii) For this purpose, utilisation shall be calculated on each system and each period separately for each country/category. In case of extension of validity/certification, percentage utilisation shall be computed separately for the quantity for which certification/validity has been extended.

(iii) All forfeited EMD/BG shall be deposited into a Public Deposit account of Government to be operated in such manner as Government notifies from time to time.

(iv) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise these fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlement in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

(v) A notice for show cause shall be issued before forfeiture.

(17) Appeal against forfeiture of EMD/BG.

An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by ED, TEXPROCIL under para 16 above may appeal before the Textile Commissioner within 15 days of receipt of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of such representation give a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he may also take into consideration force majeure conditions if any. He may also take into consideration the promptness in surrendering of unutilised entitlements during their validity. For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officer designated by him. He shall also give an opportunity for personal hearing if requested for the appellant.

(18) Handloom Products.

Notwithstanding anything contained anywhere above, quota for Handloom products shall be allotted on the following basis :

System	Percentage
PPE	40%
FCFS	30%
CRE	30%

(i) Conditions for PPE and FCFS shall ordinarily be applicable for Handloom quota mutatis mutandis.

(ii) There shall be a Handloom Quota Administrative Committee to oversee the implementation of this Policy, including granting of relaxations to the provisions of the policy so far as applicable for Handloom products. With the following composition :

- DS/Dir. (Exports)—Chairman.
- ED (Texprocil)—Member
- ED HEPC—Member
- Textile Commissioner or his representative—Member.
- Secretary Textiles Committee or his representative—Member.
- JDC (HL)—Member.

(iv) Upto 10% of FCFS quota may be reserved for PSF by the HQAC.

(19) Clearance by Customs

(i) Products under restraint :

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the TEXPROCIL or any other appropriate agency designated for this purpose.

(ii) Handloom Products :

In so far as export of all handloom fabrics/made-ups corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in Part-2 of the combination form.

(iii) Made-ups falling under "India item"

In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for export to USA, EEC, Canada, Austria, Sweden, Finland and Norway on the basis of appropriate certificate issued by the Officers of the Development Commissioner (Handicrafts).

(20) Export Certificate, Certificate of Origin and Visa.—The following certification required under the relevant Bilateral Textile Agreement will be issued by TEXPROCIL or any other body duly authorised in this behalf.

(i) USA :

Visa for all millmade/powerloom fabrics and made-ups consignments of commercial value and visa for handloom made-ups excluding floor coverings.

(ii) EEC

- (a) Export Certificate and certificate of origin for all restrained items of powerloom/millmade origin.
- (b) Certificate of origin for non-restrained items of powerloom/millmade/knitted origin.

(iii) CANADA:

Export Certificates for worsted fabrics of millmade/powerloom/knitted origin which are subject to restraint, except for consignments valued at less than Canadian dollar 500.

(iv) AUSTRIA:

Export certificates for fabrics/made-ups of powerloom/millmade origin subject to surveillance.

(v) SWEDEN:

Export Certificate for all made-ups of millmade/powerloom/knitted/crocheted origin under quantitative restraint.

(vi) NORWAY:

Export Certificate/Certificate of Origin in respect of bedlinen of powerloom and millmade origin under Category 7

21. Handloom Exempt Certificate

In the case of export of all handloom fabrics/made-ups corresponding to restrained items to Canada, cotton handloom (textile fabrics/made-ups to Austria all handloom fabrics and made-ups to EEC and the USA, handloom made-ups to Sweden and handloom bedlinen to Norway, the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

(22) Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving notice.

(23) The addresses of the concerned Export Promotion Councils and the Offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :

1. Office of the Textile Commissioner,
New C.G.O. Building, New Marine Lines,
Post Box No. 11500,
Bombay-400020.
2. The Cotton Textiles Export Promotion Council,
Engineering Centre,
5th Floor, 9 Mathew Road, Bombay-400004.
3. Silk & Rayon Textiles Export Promotion Council,
Resham Bhavan, Veer Nariman Road, Bombay-400020.
4. The Wool & Woollen Export Promotion Council,
512/714, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi-110001.
5. Carpet Export Promotion Council,
Shop No. B-115, Sector XVIII,
Post Office Noida, Distt. Ghaziabad.
6. Development Commissioner (Handicrafts),
West Block No. 7, R. K. Puram, New Delhi-110065.
Textiles Committee,
"Crystal", 79-Dr. Annie Besant Road,
Worli, Bombay-400018.

Sd/-

P. SHANKAR, Jt. Secy.